झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

एल. पी. ए. सं. 299/2023

---

1. झारखंड राज्य।

2. सचिव, सड़क निर्माण विभाग, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, धुरवा, डाक घर- धुरवा, थाना- जगन्नाथपुर, जिला-रांची, झारखंड।

3. उप सचिव, सड़क निर्माण विभाग, झारखंड सरकार, डाक घर- धुरवा, थाना- जगन्नाथपुर, जिला-रांची, झारखंड।

... ... अपीलार्थी/उत्तरदाता

बनाम

1. ब्रह्मानंद पांडे, पिता- स्वर्गीय सागर पांडे, निवासी 501/1, मालाबार, रिज़ॉर्ट अपार्टमेंट, अनंतपुर, ओवर ब्रिज के पास, डाक घर और थाना- डोरंडा, जिला रांची।

... ... प्रत्यर्थी/लिखित याचिकाकर्ता

2. महालेखाकार (ए एंड ई), डाक घर और थाना- डोरंडा, जिला रांची।

.. ... प्रोफार्मा उत्तरदाता/उत्तरदाता संख्या 4

कोरमः माननीय श्री न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद

माननीय श्री न्यायाधीश अरुण कुमार राय

अपीलकर्ता के लिए	: सुश्री सुरभी, ए. सी. से ए. ए. जी.
प्रतिवादीओं के लिए	: श्री अरुण कुमार, अधिवक्ता श्री बी. आर. रोचन, अधिवक्ता

श्री कृष्ण मुरारी, अधिवक्ता

06/तारीखः16 अप्रैल, 2024

के अनुसार सुजीत नारायण प्रसाद, जे.

1. लेटर पेटेंट के खंड 10 के तहत तत्काल अपील 2018 के डब्ल्यूपी (एस) संख्या 210 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश/निर्णय दिनांक 11.10.2022 के खिलाफ निर्देशित की जाती है, जिसके तहत, ज्ञापन संख्या 6795 (एस) में निहित सजा के आदेश को रद्द कर दिया गया है और प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता को पहले से ही बरामद की गई राशि को वितरित करने के निर्देश के साथ अलग कर दिया गया है जो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुसार सभी परिणामी लाभ प्राप्त करने का हकदार है।

2. रिट याचिका में की गई अभिवचन के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य, जिन्हें यहाँ सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है, निम्नानुसार हैं

रिट-याचिकाकर्ता को शुरू में 1981 में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन.आर.ई.पी.) योजना के तहत कनिष्ठ अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था।

27.06.1987 को, याचिकाकर्ता और कई अन्य लोगों को सहायक अभियंता के रूप में उन्नत/नियुक्त किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के मद्देनजर, रिट याचिकाकर्ता और अन्य को 1981 से ही सभी परिणामी लाभों के साथ नियमित कर्मचारियों के रूप में नियमित और व्यवहार किया जा रहा था और अंत में याचिकाकर्ता 30.09.2015 से मूल कार्यकारी अभियंता, केंद्रीय डिजाइन संगठन, सड़क निर्माण विभाग, झारखंड सरकार के रूप में सेवानिवृत्त हुआ।

2004 में किसी समय, जब रिट याचिकाकर्ता को सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य संगठन, ग्रामीण कार्य उपखंड, चतरा के रूप में तैनात किया गया था, करमा से महुदी तक सड़क के निर्माण का काम एक सावित्री कंस्ट्रक्शन, मंझगावां, इतखोरी,

चतरा और एक एम/एस विजय कुमार सिंह, जयप्रकाश नगर, इतखोरी, चतरा को 50: 50 के आधार पर आवंटित किया गया था।

काम पूरा होने के लगभग 5 साल बाद, एक एफ. आई. आर. नं. आर.सी.05(ए)/2010(आर) दिनांक 16.02.2010 भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी), 420,467,468,471 के तहत किए गए कथित अपराधों के लिए पी. सी. अधिनियम, 1988 की धार 13 (2) और 13 (1) (डी) के साथ पढ़ा गया था। 1) रत्नेश्वर राय, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, आर. डब्ल्यू. डी., चतरा,2. मेसर्स सावित्री कंस्ट्रक्शन, मंझगावां, इटखोरी, चतरा और 3. अज्ञात अन्य उपरोक्त सड़क से संबंधित कुछ बिटुमेन चालनों के खेल द्वारा बिटुमेन की खरीद के मामले में की गई कथित अनियमितता और अवैधता के लिए।

रिट याचिकाकर्ता का नाम एफआईआर में नहीं था, हालांकि 13.06.2011 को सीबीआई द्वारा प्रस्तुत अंतिम जांच रिपोर्ट में, रिट याचिकाकर्ता को भी कार्यकारी अभियंता और 2023 के 11 एलपीए नंबर 299 के पेज 3 के साथ बिना किसी भौतिक आधार के मेसर्स सावित्री कंस्ट्रक्शन के भागीदारों के रूप में शामिल किया गया था। फलतः सीबीआई रांची के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय से स्थानांतरण पर विद्वान विशेष न्यायाधीश सी.बी.आई., धनबाद के न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया।

प्रत्यर्थियों/अपीलार्थी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एक समानांतर विभागीय कार्यवाही का गठन किया। 9181 (एस) सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1930 के नियम 55 के अर्थ के भीतर किया।

उक्त आरोप पत्र अपने आप में दोषपूर्ण और अस्पष्ट और अनिर्दिष्ट होने के साथ-साथ अवैध था।उसी के साथ आरोप के बयान के साथ-साथ दस्तावेजी और मौखिक गवाहों के अलग-अलग ज्ञापन नहीं थे।

जाँच अधिकारी ने एक जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की जो रिट याचिकाकर्ता को डिप्टी के हस्ताक्षर के तहत जारी किए गए कथित दूसरे कारण बताएँ नोटिस दिनांक

28.03.2014 के साथ दी गई थी। सचिव, सड़क निर्माण विभाग, झारखंड सरकार लेकिन प्रासंगिक रिकॉर्ड की आपूर्ति के बिना।

यह रिट याचिकाकर्ता का मामला है कि दिनांक 2 का आदेश यह भी दिखाएगा कि केवल एफ. आई. आर. और आरोप पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर, याचिकाकर्ता को अनुमान और अनुमान द्वारा दोषी घोषित किया गया है और इसलिए आरोप तैयार करने के चरण से लेकर उपरोक्त रिपोर्ट/आदेश प्रस्तुत करने के बाद यांत्रिक द्वितीय कारण दिखाएं नोटिस जारी करने तक की पूरी कार्यवाही कानून में दूषित है, क्योंकि यह न केवल दिनांक 1 के प्रतिवादी परिपत्र का उल्लंघन है, बल्कि आधिकारिक जनादेश का भी उल्लंघन है।

कि उपरोक्त परिस्थितियों में, रिट याचिकाकर्ता ने अपने दिनांकित पत्र 28.07.2015 के माध्यम से विरोध सह दूसरा कारणदर्शक जवाब दायर किया, जिसमें उसे आरोपों से मुक्त करने या वैकल्पिक आपूर्ति दस्तावेजों में अनुरोध किया गया था।लेकिन चूंकि उनकी आपूर्ति नहीं की गई थी, इसलिए उन्होंने आर. टी. आई. के तहत भी आवेदन दायर किया।हालाँकि, उन्हें कभी भी गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए प्रदान नहीं किया गया था।

प्रतिवादीओं ने अंततः अधिसूचना संख्या 6795 (एस) दिनांक 29.09.2015 के माध्यम से आदेश पारित किया, जिसमें निम्नलिखित दंड दिए गएः

(1) उनके पद के वेतनमान के सबसे निचले स्तर तक कमी।

(2) सरकारी राजस्व की आनुपातिक हानि राशि की वसूली।

30.09.2015 से सेवानिवृत्ति के लगभग एक वर्ष के बाद, रिट याचिकाकर्ता की केवल 90 प्रतिशत अस्थायी पेंशन को दिनांकित 09.08.2016 के आदेश के अनुसार मंजूरी दी गई थी और अभी भी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। नतीजतन, रिट याचिकाकर्ता को दोहरी खतरे के कारण पेंशन के रूप में केवल मामूली राशि मिल रही है, यानी पहले सजा के आदेश दिनांक 29.09.2015 और फिर अस्थायी पेंशन के आदेश दिनांक 09.08.2016 के आधार पर।

उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने अपने दिनांकित पत्र 05.12.2017 के माध्यम से विरोध दर्ज किया जिसमें उसने कहा है कि जमानत के आदेश के अनुसार आनुपातिक नुकसान की राशि पहले ही सी. बी. आई. न्यायालय में जमा की जा चुकी है और इसलिए 300 दिनों की अर्जित अवकाश राशि को रोककर पेंशन लाभ से किसी भी कटौती का सवाल कानूनी और वैध नहीं है। नतीजतन, उसी के साथ-साथ पेंशन के अलग-अलग अवशिष्ट को जारी करने की प्रार्थना की गई है।

इसके बाद, रिट याचिकाकर्ता ने 2018 की डब्ल्यूपी (एस) संख्या 210 के रूप में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांकित 11.10.2022 के आदेश के माध्यम से, ज्ञापन संख्या 6795 (एस) में निहित 29.09.2015 के दंड के आदेश को रद्द कर दिया गया है और प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभ प्राप्त करने का हकदार मानते हुए पहले से बरामद राशि को वितरित करने के निर्देश के साथ अलग कर दिया गया है।विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुसार जिसके खिलाफ वर्तमान पत्र पेटेंट अपील दायर की गई है।

3. तथ्यात्मक पहलू से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता सेवा में रहते हुए एक आपराधिक मामले के अधीन था, जिसके आधार पर एक विभागीय कार्यवाही भी शुरू की गई थी। दोनों कार्यवाहियों में अलग चला गया। विभागीय कार्यवाही को प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता से नुकसान की राशि की वसूली के निर्देश के साथ प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता को वेतनमान के सबसे निचले स्तर पर वापस करने के दंड के आदेश में समाप्त कर दिया गया है।

प्रत्यर्थी/रिट याचिकाकर्ता ने इससे व्यथित होने के कारण, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर 2018 की डब्ल्यू. पी. (एस) संख्या 210 के रूप में रिट याचिका दायर करके इसे चुनौती दी है क्योंकि आधार के अनुसार, साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिसके कारण प्रत्यर्थी/रिट याचिकाकर्ता गंभीर रूप से पूर्वाग्रहग्रस्त हैं।विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी से मुलाकात की थी और जवाबी शपथ पत्र पर विचार करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों

का उल्लंघन हुआ है और इस तरह, विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया है और खारिज कर दिया गया है जिसके खिलाफ वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी गई है।

4. सुश्री सुरभी, एएजी-II की विद्वत एसी ने तर्क के दौरान प्रस्तुत किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश भले ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, फिर भी अपचारी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकरण के समक्ष मामले को प्रेषित करने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा नहीं करने के बाद, त्रुटि हुई है।

5. प्रत्यर्थी/रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण मुरारी ने विवादित आदेश का बचाव किया है और प्रस्तुत किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने सभी तथ्यों पर विचार किया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है और निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विभागीय कार्यवाही के दौरान एक गंभीर दुर्बलता हुई है, इसलिए, यदि उस बहाने सजा के आदेश को रद्द कर दिया गया है तो इसे त्रुटि से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है। हालाँकि, जहाँ तक आधार या मामले को हटाने का संबंध है, तर्क दिया गया है कि गलती/चूक के लिए अपीलार्थी/प्रत्यर्थी की ओर से प्रतिबद्ध, प्रत्यर्थी/रिट याचिकाकर्ता को पीड़ित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

6. इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष पर गौर किया है।

7. तथ्य जो इस मामले में विवाद में नहीं है, वह यह है कि प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता को उस अवधि के दौरान विभागीय रूप से आगे बढ़ाया गया था जब प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ एक आपराधिक मामला भी चल रहा था। प्रत्यर्थी/रिट याचिकाकर्ता ने जांच में भाग लिया और भले ही याचिका प्रासंगिक दस्तावेजों की गैर-आपूर्ति के लिए ली गई थी या साक्ष्य को पेश करने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन चूंकि जांच अधिकारी द्वारा इसे ध्यान में नहीं रखा गया है और आरोप साबित पाया गया है जिसके आधार पर सजा दी गई है।

8. विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए और **अरुण कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य और अन्य, के डब्ल्यू. पी. (एस) संख्या 5205** के मामले

में दिए गए फैसले पर भरोसा किया है। 2018 में पारित सजा के आदेश को रद्द कर दिया है और अलग कर दिया है।इस अपील में भी यही चुनौती दी गई है।

9. अपीलार्थी-राज्य ने प्रस्तुत किया है कि इस तथ्य को स्वीकार करते हुए भी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है, तो प्रत्यर्थी/रिट याचिकाकर्ता द्वारा की गई अनियमितता के संबंध में सही अंत तक पहुंचने के लिए, मामले को अनुशासनात्मक प्राधिकरण के समक्ष आरोप की सत्यता का परीक्षण करने के उद्देश्य से प्रेषित किया जाना चाहिए था जैसा कि प्रत्यर्थी/रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाया गया है।

10. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि यदि किसी अपचारी कर्मचारी के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही शुरू की जाती है, तो उसे सही अंत देना आवश्यक है और यदि विभागीय कार्यवाही की परिणति पर पारित किया जा रहा दंड का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों या अनुशासन और आचरण नियम के प्रासंगिक प्रावधान के उल्लंघन से ग्रस्त है, भले ही नियुक्ति प्राधिकरण अच्छी तरह से हो। उपरोक्त नियम से परिचित लेकिन उसकी अवहेलना करते हुए, विभागीय कार्यवाही जारी रही है और यदि दंड का आदेश पारित किया गया है, तो क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा की गई गलती के लिए, क्या न्यायालय के लिए उचित होगा कि वह अपचारी कर्मचारी को आगे विभागीय कार्यवाही की कठोरता का सामना करने के लिए मामले को प्रेषित करे।

11. इसमें सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1930 के नियम 55-ए के प्रावधान के संबंध में संदर्भ दिया जाना आवश्यक है, जिसमें नियमित विभागीय कार्यवाही के दौरान आयोजित की जाने वाली आवश्यकता के बारे में विवरण प्रदान किया गया है।तैयार संदर्भ के लिए, नियम, 1930 के नियम 55-ए के प्रावधान को निम्नानुसार संदर्भित किया जा रहा हैः

> *"[नियम-55-ए।*
>
> *नियम 55 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियम 49 के खंड (i), (ii), या (iv) में निर्दिष्ट दंड अधिरोपित करने वाला कोई आदेश (उन तथ्यों के आधार पर आदेश के अलावा जो आपराधिक न्यायालय या*

न्यायालय-मार्शल द्वारा उसे दोषी ठहराते हैं, या उस पद के लिए उसकी अयोग्यता के आधार पर उसे उच्च पद पर पदोन्नति के लिए प्रतिस्थापित करने वाला आदेश) किसी भी सरकारी कर्मचारी पर, जिसके लिए ये नियम लागू होते हैं, तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे कोई अभ्यावेदन करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया हो जो वह करना चाहे और ऐसा अभ्यावेदन, यदि कोई हो, आदेश के समक्ष विचार में नहीं लिया गया हो। पारित किया जाता हैःबशर्ते कि इस नियम की अपेक्षाओं को पर्याप्त कारणों से लिखित रूप में पुनर्गठित किया जा सकता है, जहां उनका पालन करने में कठिनाई होती है और जहां उन्हें संबंधित अधिकारी के साथ अन्याय किए बिना माफ किया जा सकता है।"

12. इसमें आगे यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के मामले में दिए गए निर्णय पर भी विचार किया है। **उत्तर प्रदेश और अन्य बनाम सरोज कुमार सिन्हा (2010) 2 एस. सी. सी. 772** जिसमें सुसंगत दस्तावेजों की आपूर्ति न होने के आधार पर, यदि कोई दंड लगाया जा रहा है, तो उसे उचित नहीं कहा जा सकता है। संबंधित अनुच्छेद, अर्थात उक्त फैसले के अनुच्छेद-28 से 31 का उल्लेख नीचे किया जा रहा हैः

***"28.** अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण में कार्य करने वाला एक जांच अधिकारी एक स्वतंत्र न्यायनिर्णायक के पद पर होता है।उसे विभाग/अनुशासनात्मक प्राधिकरण/सरकार का प्रतिनिधि नहीं माना जाता है।उनका कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करना है, यहां तक कि अपचारी अधिकारी की अनुपस्थिति में में भी यह देखने के लिए कि क्या अप्रमाणित साक्ष्य यह मानने के लिए पर्याप्त है कि आरोप साबित हुए हैं। वर्तमान मामले में उपरोक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।चूंकि किसी मौखिक साक्ष्य की जांच नहीं की गई है, इसलिए दस्तावेजों को साबित नहीं किया गया है, और इस निष्कर्ष पर विचार नहीं किया जा सकता है कि प्रतिवादीओं के खिलाफ आरोप साबित हो गए हैं।*

***29**. उपरोक्त के अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के आधार पर विभागीय जांच प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुसार की जानी थी।यह प्राकृतिक न्याय के नियमों की एक बुनियादी आवश्यकता है कि एक कर्मचारी को किसी भी कार्यवाही में सुनवाई का उचित अवसर दिया जाए जो कर्मचारी पर लगाए जाने वाले दंड में समाप्त हो सकता है।*

***30**. जब सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच की जाती है तो इसे एक आकस्मिक अभ्यास के रूप में नहीं माना जा सकता है।जाँच की कार्यवाही भी बंद दिमाग से नहीं की जा सकती है।जाँच अधिकारी को पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए।प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न केवल न्यायाधीश किया गया है, बल्कि स्पष्ट रूप से किया गया है।प्राकृतिक न्याय के नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक सरकारी कर्मचारी के साथ ऐसी कार्यवाही में निष्पक्ष व्यवहार किया जाए जो बर्खास्तगी/सेवा से हटाने सहित सजा के अधिरोपण में परिणत हो सकती है।*

***31**. शौघनेसी बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका में [97 एल एड 956:345 यूएस 206 (1952)] (जैक्सन, जे.), संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कहा है:(एल. एड. पी. 969) प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और नियमितता स्वतंत्रता का अनिवार्य सार है।गंभीर मूल कानूनों को सहन किया जा सकता है यदि वे निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से लागू किए जाते हैं।"*

13. इसमें, विद्वान एकल न्यायाधीश राज्य के अभिवचन की सराहना के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है क्योंकि प्रासंगिक दस्तावेज साबित नहीं हुए थे और यहां तक कि प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता को पर्याप्त और पर्याप्त अवसर भी प्रदान नहीं किया गया था, जिसके कारण विद्वान एकल न्यायाधीश ने विवादित आदेश में हस्तक्षेप किया और साथ ही जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में आदेश किए गए निष्कर्ष में भी हस्तक्षेप किया।

14. अपीलार्थी/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रश्न उठाया गया है कि इस तथ्य को स्वीकार करते हुए भी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, तब भी प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद सही निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से संबंधित प्राधिकारी के समक्ष मामला प्रेषित किया जाना चाहिए था।

15. लेकिन, इसमें, उपरोक्त तथ्य को नियमित रूप से लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निपटा जाना है, लेकिन तथ्यों और परिस्थितियों पर आने से पहले, इसे पंजाब में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय बैंक और अन्य बनामकुंज बिहारी मिश्रा (1998) 7 एस. सी. सी. 84 जिसमें अनुच्छेद -18,19 और 21 में यह देखा गया है जो नीचे दिया गया हैः

> ***"18.*** *विनियमन 6 के तहत, जांच की कार्यवाही या तो एक जांच अधिकारी द्वारा या स्वयं अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा की जा सकती है। जब जाँच अधिकारी द्वारा जाँच की जाती है, तो उसकी रिपोर्ट अंतिम या निर्णायक नहीं होती है और अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त नहीं होती है।अनुशासनात्मक कार्यवाही अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय के साथ समाप्त हो जाती है।यह अनुशासनात्मक प्राधिकरण है जो जुर्माना लगा सकता है न कि जांच अधिकारी।जहाँ अनुशासनात्मक प्राधिकारी स्वयं जाँच करता है, वहाँ उसके द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच अधिकारी के दृष्टिकोण से भिन्न होता है और एक अलग निष्कर्ष पर आने का प्रस्ताव करता है, तो इस बात का कोई कारण नहीं है कि सुनवाई का अवसर क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।यह सबसे अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा कि जहां आरोपित अधिकारी जांच अधिकारी के समक्ष सफल होते हैं, वे उस प्राधिकरण के समक्ष अनुशासनात्मक प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने से वंचित हो जाते हैं, जो जांच अधिकारी की रिपोर्ट से अलग होता है और अपराध का निष्कर्ष दर्ज करते समय अधिकारी को सजा देता है।हमारी राय में, ऐसी किसी भी स्थिति में,*

आरोपित अधिकारी को आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष दर्ज करने और सजा देने से पहले अनुशासनात्मक प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलना चाहिए।यह जांच के पहले चरण के एक भाग के रूप में किया जाना आवश्यक है जैसा कि करुणाकर मामले [(1993) 4 एस. सी. सी. 727 में समझाया गया हैः1993 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 1184:(1993) 25 एटीसी 704]।

19. *उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह होगा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को विनियमन 7 (2) में पढ़ा जाना चाहिए।इसके परिणामस्वरूप, जब भी अनुशासनात्मक प्राधिकरण किसी भी आरोप के लेख पर जांच प्राधिकरण से असहमत होता है, तो इस तरह के आरोप पर अपने स्वयं के निष्कर्ष दर्ज करने से पहले, उसे इस तरह की असहमति के लिए अपने अस्थायी कारणों को दर्ज करना चाहिए और अपचारी अधिकारी को अपने निष्कर्ष दर्ज करने से पहले प्रतिनिधित्व करने का अवसर देना चाहिए।जाँच अधिकारी की रिपोर्ट जिसमें उसके निष्कर्ष शामिल होंगे, उन्हें सूचित करना होगा और अपचारी अधिकारी के पास जाँच अधिकारी के अनुकूल निष्कर्ष को प्रतिग्रहण करना करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी को मनाने का अवसर होगा।प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, उस प्राधिकरण की आवश्यकता होती है जिसे अंतिम निर्णय लेना होता है और जुर्माना लगा सकता है, ताकि कदाचार के आरोपी अधिकारी को अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा अधिकारी के खिलाफ बनाए गए आरोपों पर अपने निष्कर्ष दर्ज करने से पहले अभ्यावेदन दायर करने का अवसर दिया जा सके।*

21. दोनों प्रतिवादी 31-12-1983 पर सेवानिवृत्त हुए।इन अपीलों विचाराधीनता रहने के दौरान, मिश्रा की मृत्यु 6-1-1995 पर हुई और उनके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड में लाया गया।अपचारी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति को 14 साल से अधिक समय बीत चुका है।इसलिए, यह न्यायाधीश के हित में नहीं होगा कि इस स्तर पर मामलों को एक और

पारी की शुरुआत के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण को भेज दिया जाए।इसलिए, हम ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं करते हैं और इन अपीलों को खारिज करते हुए, हम उच्च न्यायालय के उन फैसलों की पुष्टि करते हैं जिन्होंने जुर्माना लगाने के आदेशों को दरकिनार कर दिया था और अपीलार्थियों को प्रतिवादीओं को सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने का निर्देश दिया था।हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।"

16. उक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया है कि जांच अधिकारी के निष्कर्ष के साथ अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष के साथ मतभेद के मुद्दे पर, जिसका पालन किया जाना है, उन परिस्थितियों में, यदि इसका पालन नहीं किया गया है, चाहे कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद, क्या उक्त प्रक्रिया का पालन करने के लिए मामले को भेजना उचित होगा।माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करते हुए खुशी हुई है कि नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से की गई गलती के कारण, अपचारी कर्मचारी को नई विभागीय कार्यवाही की कठोरता का सामना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।17. यह न्यायालय वर्तमान तथ्य में उपरोक्त तथ्यात्मक पहलू को लागू करता है, जिसमें विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी जिसमें सजा का आदेश पारित किया गया था जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 11.10.2022 आदेश के माध्यम से रद्द कर दिया गया है।

18. सवाल यह होगा कि जब कानून अपचारी कर्मचारी को दिए जाने वाले अवसर का ध्यान रखते हुए विभागीय कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है और भले ही अनुशासनात्मक या जांच अधिकारी इसका पालन नहीं कर रहा हो, तो इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण के अनुसार, गलती अनुशासनात्मक प्राधिकरण के पास है और कानून अच्छी तरह से तय किया गया है कि संबंधित पक्ष द्वारा किए गए किसी भी गलत काम के लिए, पीड़ित को ***पंजाब राष्ट्रीय बैंक और अन्य बनामकुंज बिहारी मिश्रा (ऊपर)***, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार अधीन नहीं होने दिया जा सकता है। विशेष रूप से अनुच्छेद -21 में इस प्रकार किया गया अवलोकन जो पहले ही ऊपर उद्धृत किया जा चुका है।

19. इसमें, प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप के समर्थन में किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी।इसके अलावा, प्रत्यर्थी/रिट याचिकाकर्ता को प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान नहीं किए गए थे जो उसके द्वारा पूछे गए थे ताकि वह अपने मामले का ठीक से बचाव कर सके जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ, इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि प्रत्यर्थी/रिट याचिकाकर्ता को लगभग 8 वर्षों से विभागीय कार्यवाही की कठोरता का सामना करना पड़ा है, और उन परिस्थितियों में, यदि मामला प्राधिकरण के समक्ष प्रेषित किया जाएगा। नए सिरे से विभागीय कार्यवाही शुरू करना कठोर होगा और प्रतिवादी/रिट याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं होने पर उसे फिर से विभागीय कार्यवाही की कठोरता का सामना करना पड़ेगा।

20. उपरोक्त तर्क के आधार पर इस न्यायालय का विचार है कि यदि विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश को रद्द करने और सजा के आदेश को दरकिनार करने के बाद मामले को नहीं हटाने का फैसला किया है, तो हमारे सुविचारित दृष्टिकोण के अनुसार इसे त्रुटि से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है।

21. तदनुसार, तत्काल अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

22. लंबित अंतर्वर्ती आवेदन (ओं), यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया०.)

(अरुण कुमार राय, न्याया०.)

सौरभ/**ए. एफ. आर.**

<u>यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।</u>